

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 82/2017

ई.सी.जी.सी लिमिटेड पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस टावर्स 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 भारत सरकार उद्यम, इसके शाखा प्रबंधक के माध्यम से, द्वितीय तल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता(वादी)

बनाम

- मैसर्स डेव एक्सपोर्ट्स प्रोपराइटर शरद दवे पुत्र स्वर्गीय श्री भंवर लाल दवे, 437, सेक्टर-11, हिरण मगरी, उदयपुर (राजस्थान) के माध्यम से
- पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड मुख्य शाखा पंचशील मार्ग, टाउन हॉल, उदयपुर शाखा प्रबंधक के माध्यम से

-----उत्तरदाता (प्रतिवादी)

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आशीष सक्सेना

उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री बी.सी. जैन

श्री वीरेन्द्र दवे

श्री ऋत्विक् डेव

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार जैन

आदेश

रिपोर्ट योग्य

14/02/2024

1. सिविल विविध मामले में दिनांक 06.01.2017 के आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता/वादी/अनावेदक द्वारा त्वरित पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जाती है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 6, जयपुर मेट्रोपोलिटन द्वारा पारित आवेदन संख्या 192/2012, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1/उत्तरदाता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश IX नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन को स्वीकार किया गया तथा सिविल वाद संख्या 271/2008 (168/2006) में याचिकाकर्ता/वादी के पक्ष में दिनांक 03.01.2012 के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया गया।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य अन्य बातों के साथ-साथ यह हैं कि याचिकाकर्ता/वादी द्वारा 13.11.2006 को ₹37,05,172/- की वसूली के लिए एक सिविल वाद दायर किया गया था, जिस पर 07.02.2004 से वाद संस्थित होने तक 11% वार्षिक ब्याज और वाद

संस्थित होने के बाद 12% वार्षिक ब्याज भी देय था। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 आवेदक ने लिखित बयान दाखिल किया है, लेकिन उत्तरदाता /प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है। पक्षों की दलीलों के आधार पर, चार मुद्दे तय किए गए। तीन गवाहों की परीक्षा के बाद, वादी का साक्ष्य 07.07.2011 को बंद कर दिया गया और उसके बाद मामले को प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए 04.08.2011 को नियत किया गया। प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से दिनांक 04.08.2011, 24.08.2011, 16.09.2011 और 16.10.2011 को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय माँगा गया। 13.10.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से शरद दवे का हलफनामा दाखिल किया गया और मामले की जिरह दिनांक 01.11.2011 को नियत की गई, लेकिन दिनांक 01.11.2011 को गवाह अनुपस्थित रहा और मामले की सुनवाई दिनांक 25.11.2011 को नियत की गई। 25.11.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 का साक्ष्य बंद कर दिया गया और मामले की अंतिम सुनवाई दिनांक 09.12.2011 को नियत की गई। दिनांक 09.12.2011 को प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 के वकील ने कोई निर्देश न दिए जाने का अनुरोध किया और निचली अदालत ने वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के वकीलों की दलीलें सुनीं और मामले में निर्णय सुनाने के लिए 22.12.2011 की तिथि नियत की। 22.12.2011 को मामले को 03.01.2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और 03.01.2012 को निर्णय सुनाया गया।

3. उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, आवेदक/प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा आदेश IX नियम 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत दिनांक 18.09.2012 को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे 06.01.2017 को ₹2500/- के खर्च पर अनुमति प्रदान की गई और परिणामस्वरूप दिनांक 03.01.2012 के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तत्काल याचिका के आधारों पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 आवेदक ने बहस के चरण तक पूरे मुकदमे में भाग लिया है लेकिन जब मामला बहस के लिए लिया गया तो प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 के अधिवक्ता ने जानबूझकर कोई निर्देश नहीं देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कोई निर्देश नहीं देने का अनुरोध करने से पहले, उत्तरदाता संख्या 1 को तत्कालीन अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक नोटिस भेजा जाना बताया गया था उन्होंने यह भी कहा कि डिक्री पारित होने के बाद, डिक्री को अलग रखने के लिए

एक आवेदन दिया गया था, लेकिन देरी के बाद, क्योंकि प्रतिवादी / उत्तरदाता नंबर 1 द्वारा निर्धारित 30 दिनों के भीतर कोई आवेदन नहीं दिया गया था। उन्होंने चंपालाल द्वारा एल.आर बनाम कौशल कुमार एवं अन्य (एस.बी. सिविल अपील संख्या 5913/2011 दिनांक 04.07.2016) मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सीमा अवधि की गणना के लिए सीमा अधिनियम की धारा 123 लागू होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सी.पी.सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के समर्थन में देरी की माफी के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक / प्रतिवादी के लिए पर्याप्त कारण दिखाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी के आवेदन पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। उन्होंने इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि पर्याप्त कारण के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

5. उन्होंने सुनील पोद्दार और अन्य बनाम भारत संघ (2008) 2 एससीसी 326 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया और ज्ञान चंद बनाम राजस्थान ट्रैक्टर कंपनी 2006 (1) सीडीआर 788 (राजस्थान), लादू राम बनाम श्रीमती गायत्री देवी और अन्य 2004 (2) सीडीआर 1584 (राजस्थान), छीतर मल सैनी बनाम बसंती और अन्य 2014 डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) यूसी 233, मदन लाल (डी) और अन्य बनाम प्रभु दयाल और अन्य 2009 (2) आरएलडब्ल्यू 1760 (राजस्थान) के मामले में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के फैसलों पर भी भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि मलकियत सिंह और अन्य बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। जोगिंदर सिंह और अन्य 1998(2) एससीसी 206 मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना। उन्होंने दीपक एस बनाम जॉर्ज फिलिप और अन्य के मामलों का भी उल्लेख किया: एआईआर 2007 केरल 94, लछमन दास बनाम एफसीआई (2007) 146 पीएलआर 391 और ओमप्रकाश रामेश्वर पाटीदार बनाम एकबाल हुसैन 1998 (1) एमपीएलजे 349 और प्रस्तुत किया कि आवेदक/प्रतिवादी ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह से जानता था और मुकदमे के अंत में, वह अपने वकील से नोटिस के बावजूद कार्यवाही में भाग नहीं लेना चुनता है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उसने जानबूझकर कानून की प्रक्रिया को टाला था और ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय ने आवेदन को अनुमति देते हुए बहुत उदारता से काम किया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि किसी वकील ने कोई निर्देश नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह

नहीं है कि अदालत को प्रतिवादी को नया नोटिस जारी करना चाहिए और मुकदमे की सुनवाई हार जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि किसी भी वकील द्वारा कोई निर्देश न दिए जाने की दलील देने के बाद, सी.पी.सी. के तहत कोई नया नोटिस जारी करने का कोई नियम नहीं है। उन्होंने सोगानी ब्रदर्स बनाम मेसर्स कुवैत एयरवेज कॉर्पोरेशन 2009 (4) आरएलडब्ल्यू 3608 (राजस्थान) मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि एकतरफा डिक्री को रद्द करने की स्थिति में, इक्विटी को संतुलित करने के लिए कुछ कठोर शर्तें लगाई जानी आवश्यक हैं, लेकिन निचली अदालत ने उदारतापूर्वक आदेश IX नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया, मानो प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 को कोई नोटिस ही नहीं दिया गया हो।

6. उत्तरदाता /प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और कहा कि प्रतिवादी के परिवार में किसी आपात स्थिति के कारण वह 25.11.2011 को निचली अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि सी.पी.सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत उनकी याचिका में उनकी मां की बीमारी और उत्तरदाता संख्या 1 की मानसिक स्थिति के बारे में विशिष्ट कथन किए गए थे, इसलिए न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद सी.पी.सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन को उचित रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय के लिए नया नोटिस जारी करना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान मामले में, निचली अदालत ने प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी को कार्यवाही में भाग लेने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था। उन्होंने आगे दलील दी कि मल्कियत सिंह व अन्य (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, निचली अदालत ने सी.पी.सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन को सही ढंग से स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि प्रतिवादी को उचित स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, तो उद्देश्य विफल हो जाएगा, जो उसके अधिकारों से वंचित करने के समान होगा।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की समन्वय पीठ तथा अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भी विचार किया गया।

8. ऊपर बताए गए तथ्य से स्पष्ट है कि धन की वसूली के एक दीवानी मुकदमे में, वादी/

याचिकाकर्ता के पक्ष में 03.01.2012 को एक डिक्री पारित की गई थी। तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1/आवेदक ने दोनों पक्षों के साक्ष्य समाप्त होने तक निचली अदालत की कार्यवाही में भाग लिया था, लेकिन जब मामले की अंतिम सुनवाई 09.12.2011 को निर्धारित की गई, तो उत्तरदाता /प्रतिवादी संख्या 1 के वकील ने कोई निर्देश न दिए जाने का तर्क दिया।

क. हमारे सामने पहला प्रश्न यह है कि अनुदेश न देने का क्या प्रभाव होगा:

09. महत्वपूर्ण तिथियों का क्रम निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	महत्वपूर्ण खजूर	विवरण
i.	13.11.2006	वादी (यहां याचिकाकर्ता) द्वारा वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था
ii.	11.04.2007	प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से वकालतनामा दायर किया गया।
iii.	10.08.2007	प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गईं।
iv.	03.08.2010	मुद्दे तैयार किये गये।
v.	07.07.2011	वादी का साक्ष्य बंद हो गया।
vi.	04.08.2011	उत्तरदाता साक्ष्य के लिए पहली तारीख.
vii	24.08.2011 16.09.2011	प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए स्थगन।
viii	13.10.2011	प्रतिवादी के वकील द्वारा दायर डी.डब्ल्यू. शरद दवे का हलफनामा।
ix.	01.11.2011	उत्तरदाता साक्ष्य के लिए स्थगन।
X	25.11.2011	प्रतिवादी का साक्ष्य बंद हो गया।
Xi	09.12.2011	प्रतिवादी संख्या 1 के वकील द्वारा 'कोई निर्देश नहीं'। तर्क सुने गए।
Xii	22.12.2011	स्थगनों
Xiii	03.01.2012	निर्णय

Xiv	18.09.2012	प्रतिवादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन।
-----	------------	--

10. मलकियत सिंह एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, तथ्य यह था कि अपीलकर्ता के वकील ने कोई निर्देश न दिए जाने का अनुरोध किया था और निर्देश न दिए जाने के बाद कोई और नोटिस जारी नहीं किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति पर विचार करते हुए न्याय के हित में आवेदन स्वीकार कर लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ताहिल राम इस्सरदास सदारंगानी बनाम रामचंद इस्सरदास सदारंगानी 1993 सप (3) एस.सी.सी 256 के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब कोई वकील मामले से हट जाता है, तो न्याय के हित में पक्षकारों को सुनवाई की वास्तविक तिथि के लिए एक नया नोटिस भेजा जाना चाहिए था।

11. उपर्युक्त सिद्धांत से यह संकेत मिलता है कि न्याय के हित में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत दिया है कि यदि वकील द्वारा कोई निर्देश न दिए जाने का तर्क देकर पक्षकार वापस ले लिए जाते हैं, तो पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा सकता है। एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता या व्यवहारिक नियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि वकील द्वारा कोई निर्देश न दिए जाने की स्थिति में, उस पक्षकार को नोटिस जारी किया जाए जिसके वकील ने मामले से अपना नाम वापस ले लिया हो।

12. दीपक एस बनाम जॉर्ज फिलिप (सुप्रा) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मल्लिकयत सिंह और अन्य (सुप्रा) के फैसले पर विचार करने के बाद राय दी कि पक्षों की उपस्थिति की प्रक्रिया और उनकी गैर-हाजिरी के परिणाम सीपीसी के आदेश IX में विस्तृत हैं और आदेश IX यह प्रावधान करता है कि जब कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो मुकदमा खारिज किया जा सकता है लेकिन अगर मुकदमे की सुनवाई के समय प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय मुकदमे की एकपक्षीय सुनवाई कर सकता है। खंडपीठ ने संग्राम बनाम चुनाव न्यायाधिकरण कोटा एआईआर 1955 एससी 425, अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्रा कुमार और अन्य एआईआर 1964 एससी 993, रजनी कुमार बनाम सुरेश कुमार मल्होत्रा और अन्य एआईआर 2003 एससी 1322, राज कुमार बनाम के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने के बाद आदेश

IX नियम 6, 7 और 13 के दायरे पर आगे चर्चा की है। सरदारी लाल 2004 एआईआर एस.सी.डब्लू 470 और यह टिप्पणी की कि यदि वकील कोई निर्देश नहीं देता है तो नए नोटिस जारी करने के लिए कोई अनिवार्य नियम या सार्वभौमिक आवेदन का नियम नहीं है।

13. लक्ष्मण दास बनाम भारतीय खाद्य निगम (सुप्रा) के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने कहा कि केवल यह तथ्य कि एक वकील ने कोई निर्देश नहीं दिया है, ऐसे वकील के मुवक्किल को नया नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और ऐसा नोटिस जारी करने में विफलता उसके बाद शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं बनेगी।

14. पुनः, ओमप्रकाश रामेश्वर पाटीदार एवं बनाम इकबाल हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने प्रबंध निदेशक (एमआईजी) हिंदुस्तान बनाम अजीत प्रसाद तरवे एआईआर 1973 एससी 76 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि उदार दृष्टिकोण का यह अर्थ नहीं है और न हो सकता है कि गलती करने वाले आवेदकों को अपनी इच्छा से गायब होने या उपस्थित होने और अपनी सुविधा या सहूलियत के अनुसार कार्यवाही को विनियमित करने की छूट होनी चाहिए। यदि न्यायालय कानून के आदेश का पालन करता है, तो अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करने के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। कानून और न्याय दूर के पड़ोसी नहीं हैं और मुकदमा करने वालों से निकट भविष्य में अंतिम निर्णय की संभावना के बिना मुकदमा लड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। आखिरकार कई वर्षों के बाद "कोई निर्देश नहीं" का अनुरोध किया गया था।

15. इस मामले में, तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सुनवाई पूरी होने तक भाग लेने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 के वकील ने कोई निर्देश न देने का अनुरोध किया था। वकील ने 09.12.2011 को अंतिम बहस के चरण में कोई निर्देश न देने का अनुरोध किया था। 09.12.2011 को, निचली अदालत ने बहस पूरी कर ली। इस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रतिवादी/ उत्तरदाता संख्या 1/आवेदक को अपनी गवाही प्रस्तुत करने के लिए छह अवसर दिए गए थे, लेकिन वह अपनी गवाही समाप्त होने तक छह मौकों पर उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 का हलफनामा प्रतिवादी के वकील द्वारा दायर किया गया था और अदालत ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी को जिरह के लिए 01.11.2011 को

उपस्थित होना होगा। 01.11.2011 को निचली अदालत ने 25.11.2011 के लिए एक और अवसर दिया और अंततः 25.11.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 की गवाही बंद कर दी गई और मामले की अगली सुनवाई 09.12.2011 के लिए निर्धारित कर दी गई। इस प्रकार, 09.12.2011 को कोई निर्देश नहीं दिया गया।

16. विचारण न्यायालय की कार्यवाही से स्पष्ट संकेत मिलता है कि किसी भी निर्देश का तर्क विचारण के समापन के बाद दिया गया था, इस प्रकार प्रतिवादी को विचारण में भाग लेने से नहीं रोका गया था, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पूरे विचारण में भाग लिया था, इसलिए, मलकियत सिंह और अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं होता है और प्रतिवादी संख्या 1 को विचारण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी।

17. सी.पी.सी. का आदेश IX, पक्षकारों की न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थिति से संबंधित है। इसमें उन परिणामों का भी प्रावधान है जो तब लागू होंगे जब कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष उपस्थित नहीं होंगे। सी.पी.सी. के आदेश IX के नियम 1 में यह प्रावधान है कि वाद के पक्षकार(पक्षकारों) को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या वकील(वकीलों) के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक है। यदि कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है, जिसमें वादी के उपस्थित न होने पर वाद को खारिज करना भी शामिल है।

18. संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि समन की तामील सिद्ध हो जाती है, तो न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है और एकपक्षीय निर्णय पारित कर सकता है। सीपीसी के आदेश IX के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिविल मुकदमे में किसी भी पक्षकार की भागीदारी के बाद, यदि उसका वकील उपस्थित होने में विफल रहता है या "कोई निर्देश नहीं" का तर्क देता है, तो सिविल न्यायालय एकपक्षीय कार्यवाही करेगा। नियम के अभाव में, किसी भी ट्रायल कोर्ट या अपीलीय न्यायालय के लिए उपस्थिति के लिए नया नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 को उसके वकील द्वारा 09.12.2011 को "कोई निर्देश नहीं" का तर्क देने के बाद उपस्थिति का कोई नोटिस जारी न करके कोई त्रुटि नहीं की है।

बी. अब, सी.पी.सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन दायर करने की सीमा का प्रश्न आता है:

19. 03.01.2012 को डिक्री पारित होने के बाद, आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत

18.09.2012 को एक आवेदन दायर किया गया। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 123 के अनुसार, उपरोक्त परिस्थितियों में, आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत आवेदन तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ आवेदन तीस दिनों से भी अधिक समय बाद दायर किया गया। आवेदन में यह दर्शाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 को निर्णय और डिक्री पारित होने की जानकारी 30.08.2012 को हुई और 11.09.2012 को उसने निर्णय और डिक्री की प्रति प्राप्त की।

20. विलम्ब क्षमा के समर्थन में, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक आवेदन भी दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि आवेदक/प्रतिवादी संख्या 1 अपनी माँ के उपचार में व्यस्त था, हालाँकि उसकी माँ के उपचार के दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के प्रावधानों पर विचार किए बिना, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार कर लिया।

21. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि कोई भी अपील या पुनरीक्षण या आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर अपील या पुनरीक्षण आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण से न्यायालय को संतुष्ट कर देता है।

22. कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम कातिजी एआईआर 1987 एससी 1353 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब की माफी के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए: -

1. सामान्यतः किसी वादी को देरी से अपील दायर करने से कोई लाभ नहीं होता।
2. विलंब को क्षमा करने से इनकार करने पर एक उचित मामले को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जा सकता है और न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है। इसके विपरीत, जब विलंब को क्षमा किया जाता है, तो सबसे अधिक यही हो सकता है कि पक्षकारों की सुनवाई के बाद मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाए।
3. "हर दिन की देरी की व्याख्या ज़रूरी है" का मतलब यह नहीं कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं? इस सिद्धांत को तर्कसंगत और व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
4. जब पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े किए जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी

जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्ष यह दावा नहीं कर सकता कि गैर-जानबूझकर की गई देरी के कारण अन्याय होने का उसे अधिकार है।

5. यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि देरी जानबूझकर, या सदोष लापरवाही के कारण, या दुर्भावना के कारण हुई है। देरी करने से वादी को कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में, वह एक गंभीर जोखिम उठाता है।

6. यह समझना होगा कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।

23. बलवंत सिंह (मृत) बनाम जगदीश सिंह एवं अन्य 2010 (8) एससीसी 685 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 पर विचार करते समय भारत संघ बनाम राम चरण एआईआर 1964 एस.सी 215 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया और कहा कि अत्यधिक अस्पष्टीकृत विलंब के विपरीत स्पष्ट विलंब को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। विलंब केवल एक घटक है जिस पर न्यायालय को विचार करना है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय को पक्षकारों के आचरण, विलंब की क्षमा के वास्तविक कारणों और क्या आवेदक द्वारा सामान्य सावधानी और सतर्कता से कार्य करने पर इस प्रकार के विलंब को आसानी से टाला जा सकता है, को भी ध्यान में रखना चाहिए। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार विलंब की क्षमा के लिए आवेदन और कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद विलंब से दायर किए गए आवेदनों को तब तक खारिज कर दिया जाना चाहिए जब तक कि विलंब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण न दिखाया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठों के साथ-साथ सम-पीठों ने भी इन सिद्धांतों का निरंतर पालन किया है और ऐसे आवेदनों को दायर करने में देरी को या तो स्वीकार किया है या क्षमा करने से इनकार किया है। इस प्रकार, कानून की यह आवश्यकता है कि इन आवेदनों को अधिकार के रूप में और यहाँ तक कि नियमित रूप से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आवेदक को अनिवार्य रूप से ऊपर वर्णित सभी शर्तों को पूरा करना होगा; तभी न्यायालय ऐसे आवेदनों को दायर करने में देरी को क्षमा करने के लिए इच्छुक होगा।

24. विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित कारण बताए गए:-

- (i) दिनांक 25.11.2011 से 01.12.2011 तक प्रतिवादी संख्या 1 की मां बीमार थी और उन्हें इलाज के लिए गुजरात ले जाया गया था।

(ii) 02.12.2011 के बाद से प्रतिवादी संख्या 1 अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है।

यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त किसी भी कारण के समर्थन में एक भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया, इस प्रकार दावा बिना किसी दस्तावेज़ के समर्थन में किया गया था।

25. उपरोक्त विधि प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सर्वप्रथम "पर्याप्त कारण" ज्ञात करना निचली अदालत का कर्तव्य था, हालाँकि पर्याप्त कारण ज्ञात करते समय, विलंब का दैनिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे निचली अदालत से विलंब क्षमा मांगने वाले आवेदक की सद्भावना सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने इस मुद्दे पर कानून पर विचार किए बिना परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने में अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। अतः, वर्तमान मामले में, सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत आवेदन पर्याप्त विलंब के बाद दायर किया गया था और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा हेतु आवेदन के समर्थन में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः, आवेदक/प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी विलंब क्षमा का हकदार नहीं था और निचली अदालत ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करते समय गंभीर त्रुटि की है। सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत आवेदन कानून द्वारा वर्जित था और केवल विलंब के आधार पर खारिज किए जाने योग्य था।

सी. अब सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत डिक्री को रद्द करने का आधार आता है:

26. ऊपर वर्णित तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 को साक्ष्य दर्ज करने के लिए छह अवसर दिए गए थे। यह दावा किया गया था कि 25.11.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 की माँ बीमार थी और उसे अहमदाबाद (गुजरात) जाना था, लेकिन 01.12.2011 या 02.12.2011 को गुजरात से लौटने के बाद, वह अगली तारीख के बारे में जानने के लिए अपने वकील से संपर्क कर सकता था। ऐसा कोई भी तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया जिससे पता चले कि प्रतिवादी संख्या 1 ने सुनवाई की अगली तारीख, जो 09.12.2011 को निर्धारित की गई थी, के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयास किया। इसके अलावा, निर्णय 03.01.2012 को पारित किया गया था और 02.12.2011 के बाद से, प्रतिवादी ने अपने वकील से संपर्क किया है या नहीं, यह न तो तर्क दिया गया और न ही रिकॉर्ड से स्थापित हुआ। इसी तरह, 01.12.2011 को मां का इलाज कराकर

उदयपुर लौटने के बाद आवेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 कथित रूप से मानसिक बीमारी और अवसाद से ग्रस्त था, लेकिन इस आशय का कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया, जिससे यह पता चले कि यह आधार मनगढ़ंत और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। इस मामले में, प्रतिवादी को अपने खिलाफ लंबित वसूली के मुकदमे के बारे में अच्छी तरह पता था और कार्यवाही से स्पष्ट रूप से पता चला कि उसे साक्ष्य पेश करने के लिए पहले ही छह अवसर दिए जा चुके थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिवादी ने अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए इन अवसरों का उपयोग नहीं किया। प्रतिवादी, जो एक व्यवसायी है, सिविल मुकदमे के लंबित होने के बारे में अच्छी तरह जानता था और उसके अनुपस्थित होने के दावे को रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी दस्तावेज से पुष्ट नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिवादी/ उत्तरदाता क्रमांक 1/आवेदक ने आदेश IX नियम 13 सीपीसी के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए कोई आधार स्थापित नहीं किया था। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों को समझे बिना और कानूनी प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए, आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत याचिका को अत्यंत लापरवाही से स्वीकार कर लिया है।

27. आदेश IX सी.पी.सी. का नियम 13 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

"13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना - किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है, वह उस न्यायालय से, जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी, उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है; और यदि वह न्यायालय को यह समाधान कर देता है कि समन की तामील विधिवत् नहीं की गई थी, या जब वाद की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तब वह किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से निवारित था, तो न्यायालय उसके विरुद्ध डिक्री को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझे, लागत, न्यायालय में भुगतान या अन्यथा, अपास्त करने का आदेश देगा, और वाद पर कार्यवाही करने के लिए एक दिन नियत करेगा:

परन्तु जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की है कि उसे केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता, वहां उसे अन्य सभी या किसी प्रतिवादी के विरुद्ध भी अपास्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि कोई न्यायालय एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होने तथा वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था।

स्पष्टीकरण - जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है, और अपील का निपटारा इस आधार के अलावा किसी अन्य

आधार पर किया गया है कि अपीलकर्ता ने अपील वापस ले ली है, वहां एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।

28. ज्ञान चंद बनाम राज ट्रेक्टर कंपनी (सुप्रा), लादू राम बनाम गायत्री देवी (सुप्रा), रज्जो बनाम सतीश कुमार (सुप्रा), चित्तर मल सैनी बनाम बसंती और अन्य (सुप्रा) और मदन लाल बनाम प्रभु दयाल और अन्य (सुप्रा) के मामलों में, इस न्यायालय की समन्वय पीठों ने पर्याप्त कारण के मुद्दे पर समान याचिकाओं पर विचार किया और एकतरफा डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसलिए, किसी भी आवेदक के लिए एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाना आवश्यक है लेकिन यहां डिक्री को रद्द करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था। सुनील पोद्दार और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के प्रावधान पर भी विचार किया है और माना है कि संशोधित संहिता के तहत कानूनी स्थिति यह नहीं है कि प्रतिवादी को वास्तव में संहिता के आदेश V में निर्धारित प्रक्रिया और तरीके के अनुसार समन की तामील की गई थी या नहीं

(i) क्या उसे मुकदमे की सुनवाई की तारीख की सूचना थी

(ii) क्या उसके पास उपस्थित होने और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था।

एक बार ये दोनों शर्तें पूरी हो जाने पर, एकपक्षीय डिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही यह सिद्ध हो जाए कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी। यदि न्यायालय को यह विश्वास न हो कि प्रतिवादी को कार्यवाही की अन्यथा जानकारी थी और वह उपस्थित होकर वादी के दावे का उत्तर दे सकता था, तो वह संहिता के आदेश IX के नियम 13 का हवाला देकर अपने विरुद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए समन की तामील न होने का आधार प्रस्तुत नहीं कर सकता।

उपरोक्त ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि यहां प्रतिवादी संख्या 1 को न केवल सिविल मुकदमे की सूचना दी गई थी बल्कि उन्होंने दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद होने तक भाग लिया था। अंतिम बहस के समय कोई निर्देश नहीं दिया गया था। रिकॉर्ड पर एक तथ्य भी लाया गया है कि कोई निर्देश देने से पहले प्रतिवादी संख्या 1 / आवेदक के वकील ने उन्हें एक नोटिस दिया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने विधिवत प्राप्त किया था। न्यायालय का दृष्टिकोण इतना उदार नहीं होना चाहिए कि कार्यवाही में अन्य पक्ष के साथ

अन्याय हो। ट्रायल कोर्ट कानून और नियमों के आधार पर किसी भी मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए बाध्य हैं। यहां प्रतिवादी संख्या 1 को छह अवसरों के बावजूद सबूत पेश न करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं दिखाया गया था। इसके अलावा, मुकदमे को योग्यता के आधार पर तय करने के लिए सामग्री पहले से ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत डिक्री को अलग करने की दलील देने के लिए कोई भी आधार उपलब्ध नहीं था। आदेश IX के नियम 13 के तहत प्रावधान का आह्वान स्वयं कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

29. तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 25.11.2011 को प्रतिवादी संख्या 1/आवेदक अपनी माँ के इलाज के लिए अहमदाबाद गए थे, लेकिन वे 26.11.2011 को वापस लौटे और 01.12.2011 तक वे उदयपुर में ही अपनी माँ के इलाज में व्यस्त रहे। इसके बाद, कोई विशिष्ट घटना या घटनाक्रम अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार, न तो कोई कथन और न ही कोई दस्तावेज यह स्थापित करने के लिए उपलब्ध है कि 02.12.2011 के बाद प्रतिवादी संख्या 1 को किसी पर्याप्त कारण से निचली अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया था। इसलिए, निचली अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता/वादी के पक्ष में पूर्ण सुनवाई के बाद पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था।

30. वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण सराहनीय नहीं है, क्योंकि धन संबंधी डिक्री को रद्द करते समय, आदेश पारित करते समय कुछ शर्तें लगाई जानी अपेक्षित थीं, लेकिन इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने बस इस तरह से अनुमति दी है जैसे कि उसने रिकॉर्ड पर दस्तावेज लेने या साक्ष्य के लिए स्वतंत्रता देने या किसी लिखित बयान को दाखिल करने जैसे सरल आवेदन की अनुमति दी हो।

31. उपर्युक्त के मद्देनजर, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और आदेश IX नियम 13 सी.पी.सी के तहत आवेदन पर दिनांक 06.01.2017 का आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

32. परिणामस्वरूप, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 06.01.2017 का आदेश अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, सी.एस. संख्या 271/2008 (168/2006) में दिनांक 03.01.2012 का निर्णय एवं डिक्री बहाल की जाती है।

(अशोक कुमार जैन),जे

चेतना बेहरानी /308

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate